IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के तहत परिकल्पित देश में ऋण वितरण को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को गहरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई -सूचकांक) मार्च 2025 में बढ़कर 67.0 हो गया, जो एक साल पहले 64.2 था।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, जिसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।2025-26 के दौरान, वित्तीय साक्षरता के प्रसार के संदर्भ में कई पहल की गई, वित्तीय समावेशन योजनाओं की संतृप्ति के लिए और अपने ग्राहक को जानें (आरई-केवाईसी) का नवीनीकरण, अदावाकृत निधि के कुशल और तेजी से निपटान उपलब्ध कराने के लिए प्रचार करना , लीड बैंक योजना (एलबीएस) की व्यापक समीक्षा करना, डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम (ईडीडीपीई)[1] को व्यापक बनाना और इसका विस्तार करना और 2025-30 के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) का शुभारंभ करना।

2. 2025-26 के लिए एजेंडा

IV.2 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एफ़आई -सूचकांक की समीक्षा (पैराग्राफ IV.3);
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की पहुंच और समावेशन को मजबूत करना (पैराग्राफ IV.4 - IV.5); तथा
- ईडीडीपीई कार्यक्रम (पैराग्राफ IV.6) के तहत मार्च 2026 तक देश भर के 80 प्रतिशत जिलों में 100 प्रतिशत व्याप्ति प्राप्त करना।

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.3 विभाग द्वारा एफआई-सूचकांक की शुरुआत के पांच साल पूरे होने पर इसकी व्यापक समीक्षा की गई है। इस संबंध में, इसके ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

IV.4 औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच को सुविधाजनक बनाने, उद्यमशीलता गतिविधि का समर्थन करने और सीमित संपार्श्विक के साथ एमएसई के लिए अंतिम छोर तक ऋण वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से, एमएसई को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी थी।

IV.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय एमएसएमई के साथ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने, बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूकता में सुधार करने और औपचारिक वित्त तक पहुंच से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक आउटरीच पहल के रूप में एमएसएमई टाउन हॉल बैठकें आयोजित कर रहे हैं। वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास और एमएसएमई की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, जिला स्तरीय *एमएसएमई संवाद* बैठकों के माध्यम से एक अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत आउटरीच तंत्र को शामिल करने के लिए एमएसएमई टाउनहॉल बैठक ढांचे को संशोधित किया गया है, जिससे जिला और क्षेत्रीय स्तर पर हितधारकों के साथ अधिक व्यापक जुड़ाव सक्षम हो सके।

[1] पहचान किए गए जिलों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का कम से कम एक तरीका प्रदान करना, जैसे डेबिट/रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, असंरचित पूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी), *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), *आदि*।

IV.6 31 मार्च, 2026 तक, ईडीडीपीई कार्यक्रम के तहत देश भर के 80 प्रतिशत से अधिक जिलों (710 जिलों) में 100 प्रतिशत व्याप्ति हासिल की गई है।

प्रमुख घटनाक्रम

क्रेडिट डिलिवरी

प्राथमिकता क्षेत्र

IV.7 31 मार्च, 2026 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) समायोजित[2] शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) / ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीएसई) के ऋण के समतुल्य ऋण का 45.0 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, था। प्रत्येक बैंक समूह ने 2025-26 के दौरान निर्धारित 40 प्रतिशत समग्र पीएसएल लक्ष्य हासिल कर लिया है (सारणी IV.1)।

कृषि के लिए ऋण का प्रवाह

IV.8 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश ऋण प्रदान करने के लिए एक एकल खिड़की सुविधा है। 2025-26 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में परिचालित केसीसी की संख्या में 11.7 प्रतिशत की गिरावट आई है और बकाया राशि में 4.9 प्रतिशत की कमी आई है (सारणी IV.2)।

सारणी IV.1: प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	लघु वित्त बैंक	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4	5	6
2024-25	35.9 (42.3)	27.1 (44.3)	2.7 (41.8)	1.6 (84.4)	67.3 (43.6)
2025-26*	39.3 (42.8)	31.5 (47.2)	3.0 (42.0)	1.9 (78.8)	75.7 (45.0)

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएनबीसी / सीईओबीएसई के प्रतिशत हैं, इनमें से जो भी अधिक हो।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रिटर्न।

IV.9 व्याप्ति का विस्तार करने, परिचालनगत पहलुओं को सुव्यवस्थित करने और उभरती आवश्यकताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से केसीसी योजना दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई। मसौदा दिशा-निर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए हैं।

एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.10 एमएसएमई को क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाना, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई को बकाया ऋण में 2025-26 (दिसंबर 2025 के अंत तक) के

सारणी IV.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, रकम करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया आवधिक ऋण	पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2024-25	290.2	5,07,821	55,047	38,107	6,00,975
2025-26*	256.2^	4,95,596^	39,352^	36,496^	5,71,444^

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
#: चालू केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक आस्ति (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।
^: यह गिरावट मुख्य रूप से कुछ खास प्राइवेट निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछ ऐसे एक्सपोज़र को रीक्लासिफ़ाई/डीक्लासिफ़ाई करने की वजह से है जो मौजूदा केसीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक।

[2] यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और विदेशी बैंकों से संबंधित है।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, रकम लाख करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	अति लघु उद्योग		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023-24	231.9	13.3	21.3	8.6	3.8	5.3	257.0	27.3
2024-25	223.9	15.0	15.2	9.8	4.0	6.3	243.1	31.1
2024-25 (दिसंबर 2024 के अंत तक)	216.5	14.4	14.8	9.4	3.8	5.9	235.1	29.8
2025-26 (दिसंबर 2025 के अंत तक)	217.4	18.3	13.9	11.5	3.4	6.9	234.7	36.8

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रिटर्न।

दौरान 23.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 18.3 प्रतिशत थी (सारणी IV.3)।

वित्तीय समावेशन (एफ़आई)

वित्तीय योजनाओं और री-केवाईसी की परिपूर्णता के लिए अभियान

IV.11 भारतीय रिज़र्व बैंक ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं की संतृप्ति के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बैंकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभियान के दायरे का विस्तार उन सभी खातों के री-केवाईसी करने के लिए किया गया था, जिनके केवाईसी किए जाने का कार्य शेष था और इसके तहत शिकायत निवारण और अदावाकृत जमा राशियों पर जागरूकता को बढ़ावा भी दिया गया था। रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों ने अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित कई शिविरों का दौरा किया और उन्हें संबोधित किया। री-केवाईसी/केवाईसी अपडेशन के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मल्टीमीडिया अभियान चलाया गया और खातों के कवरेज में प्रगति की बारीकी से निगरानी की गई।

अदावाकृत निधि के प्रभावी और तेजी से निपटान की सुविधा के लिए अभियान

IV.12 रिज़र्व बैंक अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान अदावाकृत निधियों की वापसी और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड से पात्र दावों के समय पर निपटान की सुविधा के लिए आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान, 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' (आपका पैसा, आपका अधिकार) में भी शामिल था। अभियान के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2876 करोड़ रुपये की अदावाकृत जमा राशि का निपटान किया गया। (डेटा स्रोत: डीएफ़एस)

लीड बैंक योजना (एलबीएस) की व्यापक समीक्षा

IV.13 वित्तीय समावेशन की व्याप्ति को बढ़ाने के लिए और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने में एलबीएस की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से एलबीएस की व्यापक समीक्षा की गई। मसौदा दिशानिर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किए गए थे।

लीड बैंक की जिम्मेदारी का समनुदेशन

IV.14 वर्तमान में, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और दो निजी क्षेत्र के बैंकों (जम्मू और कश्मीर बैंक और आईसीआईसीआई

बैंक) को देश भर के 778 जिलों को कवर करते हुए लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (ईडीडीपीई) का विस्तार और गहरा होना

IV.15 ईडीडीपीई कार्यक्रम को अगस्त 2023 में सभी जिलों [केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो जिलों को छोड़कर] तक बढ़ा दिया गया था। 31 मार्च, 2026 तक, देश भर के 80 प्रतिशत से अधिक जिलों (710 जिलों) में 100 प्रतिशत व्याप्ति हासिल कर ली गई है, जिसमें 22 राज्योंऔर आठ केंद्र शासित प्रदेशों[3] के सभी जिले शामिल हैं[4]।

वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी

IV.16 वित्तीय समावेशन में बैंकों की प्रगति की निगरानी वित्तीय समावेशन की प्रगति (एमपीएफआइ) विवरणी की निगरानी के माध्यम से की जाती है। दिसंबर 2025 के अंत तक इन मापदंडों पर बैंकों द्वारा हासिल की गई प्रगति नीचे सारणी IV.4 में प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई -सूचकांक)

IV.17 रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन की सीमा का आकलन करने के लिए तीन उप-सूचकांकों (अर्थात् पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता) को शामिल करते हुए एक संयुक्त वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) विकसित किया है। बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर, एफ़आई -सूचकांक मार्च 2025 में 67.0 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया, जिसमें उपयोग और गुणवत्ता के नेतृत्व में सभी आयामों में लाभ हुआ, जो गहन वित्तीय समावेशन और निरंतर वित्तीय साक्षरता प्रयासों को दर्शाता है (चार्ट IV.1 और IV.2)।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफ़आई): 2025-30

IV.18 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफ़आई): 2025-30, जिसे वित्तीय स्थिरता और

चार्ट IV.1: एफ़आई - सूचकांक और उप -सूचकांक (मार्च के आखिर में)

(अनुक्रमणिका)

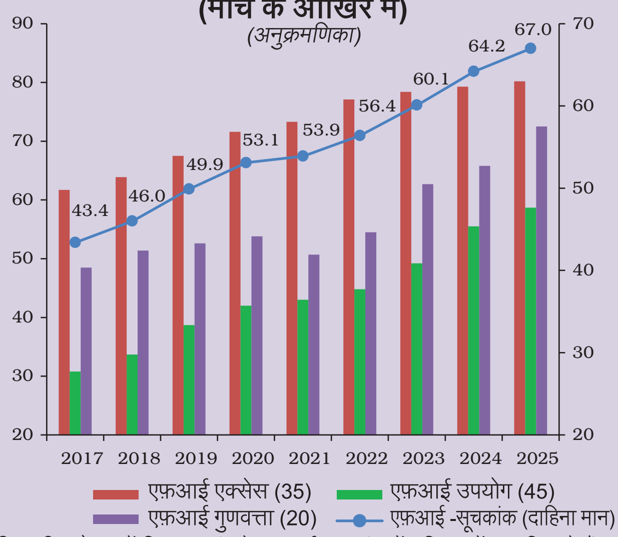

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफ़आई सूचकांक में प्रतिशत में भार दिखाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.2: एफ़आई-सूचकांक की वृद्धि में उप-सूचकांकों का योगदान (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत बिंदु)

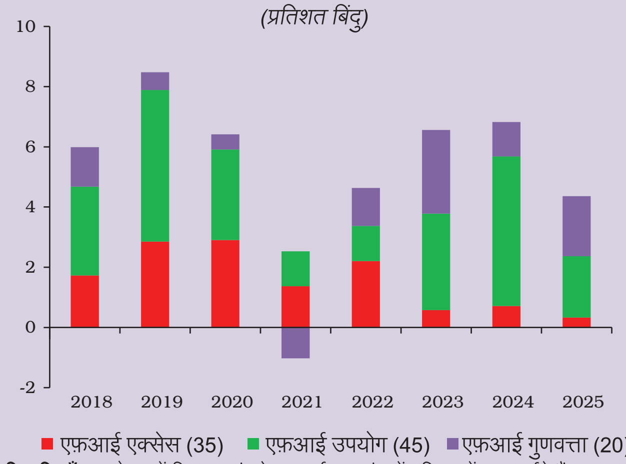

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफ़आई-सूचकांक में प्रतिशत में भार दर्शाते हैं।
2. 2021 के दौरान एफ़आई-गुणवत्ता का नकारात्मक योगदान वित्तीय साक्षरता गतिविधियों में कमी के कारण था।
स्रोत: आरबीआई।

3 केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब।

4 दिल्ली , चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी

विवरण	दिसंबर 2024[&]	दिसंबर 2025[$]		
1	2			3
	कुल	ग्रामीण	शहरी*	कुल
बैंक के अपने स्टाफ द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट्स की संख्या - ब्रांच	56,579**	57,319 (34)	1,12,870 (66)	1,70,189
बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट्स की संख्या ^ (फिक्स्ड पॉइंट बीसी आउटलेट) ^^	-	7,56,840 (64)	4,18,410 (36)	11,75,250
बीएसबीडीए - कुल (लाख में संख्या)	7,201	3,509 (48)	3,795 (52)	7,304
कुल बीएसबीडीए में से महिला खाताधारकों की संख्या (लाख में)	-	1,943 (48)	2,081 (52)	4,024
बीएसबीडीए - कुल (राशि करोड़ में)	3,04,715	1,76,105 (51)	1,69,372 (49)	3,45,477
बीएसबीडीए में कुल रकम में से, महिला खाताधारकों के खातों में रकम (करोड़ में)	-	1,05,842 (51)	1,00,253 (49)	2,06,095
बीएसबीडीए में उपलब्ध ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	45	13 (41)	19 (59)	32
कुल में से, बीएसबीडीए में महिलाओं द्वारा ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	-	7 (41)	10 (59)	17
बीएसबीडीए में उपलब्ध ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	548	174 (42)	240 (58)	414
कुल में से, बीएसबीडीए में महिलाओं द्वारा ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	-	83 (43)	110 (57)	193
आईसीटी- बीसी -कुल लेन-देन (संख्या लाख में) #@	29,944	23,778 (60)	15,635 (40)	39,413
कुल आईसीटी -बीसी लेनदेन में से, महिला बीसी एजेंट्स द्वारा किए गए लेनदेन (संख्या लाखों में) #@	-	4,288 (62)	2,632 (38)	6,920
आईसीटी- बीसी-कुल लेन-देन (राशि करोड़ में) #	10,73,073	6,90,093 (58)	4,99,674 (42)	11,89,767
कुल आईसीटी -बीसी लेनदेन में से, महिला बीसी एजेंटों द्वारा किए गए लेनदेन (राशि करोड़ में) #	-	1,36,844 (59)	94,441 (41)	2,31,285

बीसी : बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट. बीएसबीडीए: बुनियादी बचत बैंक जमा खाते। ओडी: ओवरड्राफ्ट।

आईसीटी : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी - : उपलब्ध नहीं

&: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा किए गए वित्तीय समावेशन योजना (एफ़आईपी) रिटर्न पर आधारित। एफ़आईपी रिटर्न मार्च 2025 से बंद कर दिया गया है।

$: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों (टियर III और IV) द्वारा जमा किए गए एमपीएफ़ रिटर्न पर आधारित।.

*: शहरी में अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्र शामिल हैं।

**: यह डेटा गांवों में बैंक के अपने कर्मचारियों (यानी, शाखाओं) द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट के लिए है।

^: पिछली वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) में, बीसी आउटलेट (गांवों और शहरी स्थानों) की कुल संख्या 17,23,303 बताई गई थी, जो दिसंबर 2024 के एफ़आईपी रिटर्न (पीएसबी, पीवीबी और आरआरबी द्वारा जमा) पर आधारित थी। दिसंबर 2025 के एमपीएफ़आई रिटर्न के अनुसार संबंधित संख्या 14,77,594 थी। बीसी आउटलेट की संख्या में यह कमी एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा संशोधित रिपोर्टिंग और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बीसी नेटवर्क के पुनर्संरेखण के कारण हुई।

^^: बीसी द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट, यानी, फिक्स्ड पॉइंट बीसी आउटलेट जो सप्ताह में 5 दिन, प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे काम करते हैं।

#: वित्तीय वर्ष की शुरुआत से किए गए लेनदेन।

@: वित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों प्रकार के लेनदेन।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल हिस्सेदारी (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. अनंतिम डेटा।

स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफ़आईपी विवरणियाँ।

विकास परिषद (एफ़एसडीसी-एससी) की उप-समिति द्वारा अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था उसे औपचारिक रूप से 1 दिसंबर, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा उद्घाटन किया गया। यह रणनीति पूर्ववर्ती रणनीति (एनएसएफआई: 2019-24) की उपलब्धियों पर आधारित है और लोगों की भलाई के लिए वित्तीय समावेशन पारिस्थितिकी तंत्र को और गहरा और मजबूत करते हुए मांग और आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टि और मार्ग स्थापित करने का प्रयास करती है (बॉक्स IV.1)।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का आयोजन

IV.19 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) 2026, रिज़र्व बैंक की एक वार्षिक पहल, 9 से 13 फरवरी, 2026 के दौरान "केवाईसी - सुरक्षित बैंकिंग के लिए आपका पहला कदम" विषय पर मनाया गया, ताकि केवाईसी और खाता अनुशासन के महत्व पर जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। सप्ताह के दौरान टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटडोर होर्डिंग के माध्यम से एक केंद्रीकृत जन-मीडिया अभियान चलाया गया। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी इस विषय पर स्थानीय अभियान चलाए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। केवाईसी से संबंधित जागरूकता संदेशों को 22 फरवरी, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन में शामिल किया गया था।

बॉक्स IV.1: वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई): 2025-30

एनएसएफ़आई : 2025-30 का मकसद वित्तीय समावेशन की कोशिशों को बढ़ाना है ताकि कई तरह की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक आसान और असरदार पहुंच हो, साथ ही वित्तीय साक्षरता, ग्राहक जागरूकता और ग्राहक सुरक्षा भी हो । यह एक सहक्रियात्मक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण अपनाने और अंतिम छोर तक पहुँच की गुणवत्ता और सततता को बेहतर बनाने, और कौशल और रोजी-रोटी की कोशिशों के साथ संपर्क के ज़रिए वित्तीय सेवाओं के असरदार इस्तेमाल पर ध्यान देने पर ज़ोर देता है।

इस रणनीति में देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पांच रणनीतिक लक्ष्य (पंच -ज्योति) और उन्हें पाने के लिए 47 कार्य बिन्दु का एक मेन्यू बताया गया है। पंच -ज्योति में ये शामिल हैं:

ए) मैं परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सेवाओं के एक न्यायसंगत, जिम्मेदार, उपयुक्त और सस्ती सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में सुधार करूँगा;

बी) महिलाओं के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन के लिए लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना और परिवारों, विशेषकर वंचित और कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समुत्थानशीलता को बेहतर बनाने के लिए विभेदित रणनीतियाँ बनाना;

सी) आजीविका, कौशल विकास और समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र और वित्तीय समावेशन के साथ उनके संबंधों में तालमेल बिठाना;

डी) वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा का इस्तेमाल एक टूल के तौर पर करना; और

ई) ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण के उपायों की गुणवत्ता और भरोसे को मज़बूत करना।

इन सिफ़ारिशों का मुख्य ज़ोर वित्तीय समावेशन के इस्तेमाल और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर है, साथ ही अंतिम छोर तक पहुँच को बेहतर बनाना और निगरानी व माप तंत्र में प्रभावशीलता और बारीकी सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है। एनएसएफ़आई :2025-30 के तहत कार्रवाई के बिंदु और समय-सीमाएँ वित्तीय क्षेत्र के नियामकों [जैसे, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए)] और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच वितरित की गई हैं; इसके साथ ही इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएफ़ई) भी शामिल हैं।

यह रणनीति वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षारता पर तकनीकी समूह (टीजीएफ़आईएफ़एल) की देखरेख में बनाई गई है। इसमें रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग हित धारकों के साथ देश भर में बातचीत की और आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; सेबी; आईआरडीएआई; पीएफ़आरडीए; नाबार्ड; एनएसडीसी और एनसीएफ़ई के साथ परामर्श किया।

स्रोत: आरबीआई।

3. 2026-27 के लिए एजेंडा

IV.20 विभाग ने 2026-27 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एनएसएफआई के तहत कार्य बिंदुओं का कार्यान्वयन: 2025-30;
- ईडीडीपीई (*उत्कर्ष* 2029) के तहत मार्च 2027 तक देश भर के सभी चिन्हित जिलों में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करना : और
- एमएसएमई में तनाव के समय पर समाधान के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा की समीक्षा की गई

4. निष्कर्ष

IV.21 रिज़र्व बैंक ने समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा । आगे बढ़ते हुए, एनएसएफआई: 2025-30 के तहत अपनाई गई रणनीति से देश में वित्तीय समावेशन को और गहरा करने की उम्मीद है।